

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

# समय



रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

# दर्शन

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

दुर्ग शहर में  
सुप्रसिद्ध  
ज्योतिषाचार्य  
गृह दुर्ग उपर्युक्त सामग्री मूल्यमान, मौद्रिक, मौशवटी की  
अनेक गुण सामान बाजार सरकारी वालों का नाम देने वाले  
पं. एम.पी. शर्मा/  
मो. 8109922001  
फोस 251/- मात्र  
पता:- श्री दुर्ग ज्योतिष कार्यालय  
सिकोला भाटा, सब्जी मार्केट के  
सामने, धमधा नाका, दुर्ग

वर्ष 06, अंक 81 पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

रायपुर, शनिवार 20 अप्रैल 2024

www.samaydarshan.in

**फिर एक बार  
मोदी सद्गार**

**₹5500 प्रति मानक बोरा  
तेंदुपत्ता की खरीदी**

**भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़**



## 21 राज्यों की 102 सीटों पर 63 प्रतिशत वोटिंग

त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80, बिहार में सबसे कम 48 प्रतिशत; बंगाल-मणिपुर में हिंसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा के पर्सन फेज में 21 राज्यों-केंद्र सांसद प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 हुई वोटिंग में 63 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। सबसे ज्यादा 80 प्रतिशत वोटिंग त्रिपुरा में हुई, जबकि सबसे कम 48 प्रतिशत वोटिंग बिहार में हुई। सीटों के विस्तृत से यह सबसे बड़ा फेज है। दो राज्यों पश्चिम बंगाल और मणिपुर में वोटिंग के दौरान हिंसा की भी हुई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी बोट डाले गए। अरुणाचल में 64 प्रतिशत और सिक्किम में 68 प्रतिशत लोगों ने राज्य में सरकार बनाने के लिए वोट डाले।

**कूचीबिहार में भाजपा-टीएमसी - जार्यकर्ताओं में पथराव**

पश्चिम बंगाल के कूचीबिहार में



इम्फाल में उपद्रवियों ने ईवीएम  
जलाई, तोड़फोड़ भी हुई

पूर्वी इम्फाल के मोइरांगकूपू में चुनाव के दौरान आगजनी की घटना समाने आई है। यहां उपद्रवियों ने ईवीएम फारम को जला दिया।

वहां इंफाल पूर्वी जिले के खुई-लाइखुटोंवी में युस्कुपू लोगों ने ईवीएम मशीन में तोड़फोड़ कर दी। इन लोगों का आरोप था कि हथियार बदल बदलायें ने उनका बोट डाल दिया। वोटिंग के दौरान मणिपुर के विष्णुपुर में भाजपा फायरिंग हुई। मणिपुर को दो लोकसभा सीटों (मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर) पर भी इस फेज में वोटिंग है।

हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। बंगाल के कूचीबिहार में पोलिंग इयूटी में लगे सौएआरएफ जवान की मौत हो गई है। अस्पताल

भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के मतदाताओं को डाल रहे हैं।

इस इलाके में गुरुवार रात भी

भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर हिंसा की और

कूचीबिहार के तुफानांज में आगजनी की। टीएमसी ने भाजपा प्रत्याशी के

की। टीएमसी

भारत दुनिया की पाँचवीं अर्थव्यवस्था का देश बना

## मोदी सरकार ने सेना का आधुनिकीकरण कर भारतीय सीमाओं को अभेद्य बनाया - संतोष पांडे

राजनांदगांव (समय दर्शन)।

भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संतोष पांडे ने आज खेंगाह व कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का व्यापक दौरा करते हुए कहा कि वर्तमान आप चुनाव देश के लिए अत्यंत महत्व के हैं, भारत के ऊजवल भविष्य को गढ़ने वाले भी हैं, व नई पीढ़ी को दिशा भी दिखाने वाले रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजादी के बाद देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाना था वह नहीं हो पाया। अंग्रेजों के आक्रमण के पहले हम विश्व के सबसे समृद्ध देश हुआ करते थे, किन्तु 200 वर्षों के अंग्रेजी शासनकाल ने हमारे देश के ताने-बाने को ध्वस्त कर दिया अंग्रेजों ने कटरचना करके भारतीय संस्कृत में पश्चिमी सभ्यता थोके जो चाल चली और देश का यह दुर्भाग्य रहा की आजादी के बाद कांग्रेस का नेतृत्व जिन हाथों में आया वे अंग्रेजीयत संस्कारों से ओतप्रोत रहे, उन्हें देश की मौलिक आवश्यकताओं व सांस्कृतिक विवास का ज्ञान नहीं था, परस्परूप



इनके लंबे शासनकाल में देश पटरी से अधूरी की अधूरी रह जाती रही। आम लोगों के चलने के लिए ना तो अच्छी सड़क बन पा रही थी, और ना ही सेना को आधुनिक हथियार मिल पा रहे थे, और उन्होंने जड़ता आ गई थी, भ्रष्टाचार खूब फ्लू-फ्लू रहा था गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर होते चले गए। विकास परियोजनाओं की जड़ में भ्रष्टाचार का नस्तर लग गया तथा वह दशकों तक

अधूरी की अधूरी रह जाती रही। आम लोगों के आधुनिक हथियार मिल पा रहे थे, और ना ही सेना को आधुनिक हथियार मिल पा रहे थे, और उन्होंने जड़ता आ गई थी, भ्रष्टाचार खूब फ्लू-फ्लू रहा था गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर होते चले गए। विकास परियोजनाओं की जड़ में भ्रष्टाचार का नस्तर लग गया तथा वह दशकों तक

को देश एक दयनीय देश के समान हो गई थी।

### मोदी की सरकार बनी, तब कही जाकर देश की माली हालत में सुधार आना प्रारंभ हुआ

श्री पांडे ने आगे कहा कि पिर देश में राम मंदिर का आंदोलन आया, राष्ट्रीय विचारों की द्वायापन हुई, फिर पहले अटल जी उसके बाद मोदी की सरकार बनी, तब कही जाकर देश की माली हालत में सुधार आना प्रारंभ हुआ।

मोदी जी ने जहां देश को आंतरिक व बाह्य खतरों से मुक्त कराया वही विकास का नया इतिहास रचा। सेना का आधुनिकीकरण किया गया एवं भारतीय सीमाओं को अभेद्य बनाया गया। आंतरिक दृष्टि से भारत को मजबूत स्थिति में ले जाते हुए दुनिया की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया विश्व के किसी भी कोने में यदि कोई भारतीय संकट में फ़सा तो उसे सुरक्षित भारत की धरती पर लाने का अभिनव

प्रयत्न हुआ।

पूरी दुनिया में भारत यह संदेश देने में सफल रहा की हम कमज़ोर नहीं हैं, एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़े हैं और यह पहचान सुनिश्चित की। आजादी के बाद पहली बार 25 कोरोड से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आये, देश की आवादी के 80 कोरोड लोगों को अनवरत रूप से मुक्त राशन देकर रोटी और समस्या का निराकरण हुआ। करोड़ों लोगों को पक्के मकान दिये गए, करोड़ों किसानों को किसान सम्माननिधि से नवाजा गया, करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर राहत पहुंचाई गई, लाखों-लाख लोगों को रोजगार के नेतृत्व देश तेजी से प्रगति पथ की ओर आगे बढ़ती हुई अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री ने दूर्दोषी के विकासित भारत के संकट को पूरा करने के लिए यह जरूरी है की इस तरह देश तेजी से प्रगति पथ की ओर आगे बढ़ती हुई अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री ने दूर्दोषी के विकासित भारत के संकट को पूरा करने के लिए यह जरूरी है की इस तरह देश तेजी से प्रगति पथ की ओर आगे बढ़ती हुई अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।



बसना (समय दर्शन)। बसना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम विध्या टांडा पारा में त्रिविद्याय अखंड रामायण कथा का आयोजन 21 अप्रैल तक रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 19/04/2024 को प्राप्त: 10 बजे कलश याता निकाली जायेगी। कलशयात्रा के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों से पथरे रामचरित मानस मंडलियों के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम चंद्र जी के जीवन चरित्र पर आधारित श्रीराम भजन गायन व कथा का वाचन किया जायेगा। ग्राम वासियों के द्वारा इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है।

बता दें कि दिनांक 19 अप्रैल को तोरण द्वारा मानस परिवार झल्ला, शीतला मानस परिवार डोंगीपाली, दिनांक 20 अप्रैल को आराधना मानस परिवार गूह्य अरांग, रागिनी मानस परिवार आडेकेरा जैजेपुर, तुलसी मानस मंडली सांसराईपाली, शारदा मानस परिवार भरदांगोंड राजनांदगांव, शिवम मानस परिवार चरीपड़ा दिवानडबरी, श्री परमेश्वर मानस परिवार सेमतरा राजिम और दिनांक 21 अप्रैल को सुर संजना मानस परिवार धमतरी, श्रीराम मानस परिवार खलाना नवापार उडीसा, आंचल मानस परिवार रिकोकला सपोस के द्वारा सुमधुर भजन की प्रस्तुति दी जायेगी। दिनांक 21 अप्रैल को पूर्णहूति के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।

बता दें कि दिनांक 19 अप्रैल को तोरण द्वारा मानस परिवार झल्ला, शीतला मानस परिवार डोंगीपाली, दिनांक 20 अप्रैल को आराधना मानस परिवार गूह्य अरांग, रागिनी मानस परिवार आडेकेरा जैजेपुर, तुलसी मानस मंडली सांसराईपाली, शारदा मानस परिवार भरदांगोंड राजनांदगांव, शिवम मानस परिवार चरीपड़ा दिवानडबरी, श्री परमेश्वर मानस परिवार सेमतरा राजिम और दिनांक 21 अप्रैल को सुर संजना मानस परिवार धमतरी, श्रीराम मानस परिवार खलाना नवापार उडीसा, आंचल मानस परिवार रिकोकला सपोस के द्वारा सुमधुर भजन की प्रस्तुति दी जायेगी। दिनांक 21 अप्रैल को पूर्णहूति के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।

कलेक्टर साहू ने ली वन विभाग की समीक्षा बैठक

## लीफआर्टिस्ट विकास शांडिल्य ने अनोखी कलाकारी से किया मतदाताओं को जागरूक



### पीपल के पते पर धर्म से ऊपर उठकर मदन करने का दिया संदेश

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश। विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास शांडिल्य के उपर उठकर मदन करने का दिया संदेश।

धर्मतरी (समय दर्शन)। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत निवाचन संघर्ष के लिए अधिकारी और अनिवार्य सेवा अंतर्गत जिले के विकास



## संपादकीय...

अलग राज्य बनाने के पीछे राजनीतिक समर्थन ही पर्याप्त नहीं, एक स्वतंत्र प्रशासनिक ईकाई स्थापित करना ही मकसद नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति अहम कारक होते हैं। आंध्रप्रदेश को भाषायी आधार पर अलग राज्य बनाने के बाद ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसी मुद्दे का व्यापक अध्ययन किया और 1955 में निष्कर्ष दिया कि अलग राज्य बनाने के लिए भाषायी ही सबसे सशक्त आधार है। राज्य सिर्फ एक प्रशासनिक ईकाई, एक अलग, स्वतंत्र सरकार ही नहीं है, वहां लोकतांत्रिक संस्थानों की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली भी भावनात्मक हो। भाषा इस संदर्भ में इसका माकूल जवाब हो सकती है।

बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिमी उप्र को एक अलग, स्वयंतर राज्य बनाने का मुद्दा उठाला है। जब मायावती 2007-12 के दौरान उप्र की मुख्यमंत्री थीं, तब भी वह इस मुद्दे पर मुखर थीं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और उनके बाद भी इसी भूक्षेत्र को 'हरित प्रदेश' नामक राज्य बनाने को आंदोलन और अभियान छेड़े गए थे। 'हरित प्रदेश' राष्ट्रीय लोकदल के महत्वपूर्ण मुद्दों में एक था। चूर्चि पश्चिमी उप्र जाट, किसान, गुर्जर बहुल आबादी का क्षेत्र है, जिनका बुनियादी पेशा कृषि है, लिहाजा 'हरित प्रदेश' नाम देने की बार-बार बात कही गई, लेकिन अब मायावती ने जो मुद्दा उठाया है, उसकी भावुकता 'हरित प्रदेश' से न जुड़ कर राजनीतिक और चुनावी अधिक है। बसपा को आम चुनाव, 2024 में कोई बड़ा फयदा मिलेगा, ऐसे

आसार नहीं हैं, क्योंकि मायावती राजनीतिक तौर पर उतनी सक्रिय भी नहीं हैं। किसी भूखंड, क्षेत्र का पुनर्गठन करनया, अलग राज्य बनाना आसान नहीं है। अलग राज्य के लिए संस्कृति, भाषा और जन-आंदोलन का होना बेहद अनिवार्य है। भाषावी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सिलसिला 1953 में शुरू हुआ, जब आंध्रप्रदेश को प्रथम भाषावी राज्य बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। तत्कालीन ऐसूर राज्य और मद्रास राज्य के हिस्सों को अलग कर 'आंध्रप्रदेश' नए राज्य का पुनर्गठन किया गया। 2013-14 में आंध्रप्रदेश का विभाजन किया गया और 'तेलंगाना' नवा, अलग राज्य बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग भारत सरकार का एक संस्थान है, जो नया, अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया सम्पन्न करता है। आयोग राज्यों के विभिन्न विवादों का भी निपटान करता है।



अलग राज्य बनाने के पीछे राजनीतिक समर्थन ही पर्याप्त नहीं, एक स्वतंत्र प्रशासनिक ईकाई स्थापित करना ही मकसद नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति अहम कारक होते हैं। आधंप्रदेश को भाषायी आधार पर अलग राज्य बनाने के बाद ही समस्याओं का

समाधान नहीं हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसी मुद्रे का व्यापक अध्ययन किया और 1955 में निष्कर्ष दिया कि अलग राज्य बनाने के लिए भाषायी ही सबसे सशक्त आधार है। राज्य सिर्फ़ एक प्रशासनिक ईकाई, एक अलग, स्वतंत्र सरकार ही नहीं है, वहां लोकतांत्रिक संस्थानों की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली भी भावनात्मक हो। भाषा इस संदर्भ में इसका माकूल जवाब हो सकती है। प्रशासन के प्रभावों का भी सवाल है। कभी प्रभावशीलता प्रशासनिक ईकाई के आकार से भी तय होती है। करीब अटाई दशक पहले 'हरित प्रदेश' गलोद का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। आज नहीं है। इसी दौर में भाषायी आधार और क्षेत्रीय इतिहास, संस्कृति के आधार पर अलग राज्यों की मांगें मुखर होने लगीं। नतीजतन झारखंड, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ राज्य बनाए गए। उनके मूल राज्य-बिहार, उपर और मध्यप्रदेश इतने विशाल राज्य थे कि विभाजन होने के बावजूद कुछ और अलग राज्यों की मांगें गूंजती रहती हैं। आवास और शहरी मामलों की संसदीय कमेटी की एक रपट में अनुमान लगाया गया था कि राष्ट्रीय जीडीपी में शहरी भारत की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत है, लिहाजा शहरी प्रभुत्व राज्य में राजनीतिक आयामों और गतिशीलता को बदल सकता है। राज्य सरकार को जो टैक्स मिलता है, उस पर भी स्वायत्त नियंत्रण इसी वर्चस्व से तय होगा। पश्चिमी उप्र का मुद्दा अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र का होगा।

तेलंगाना भी खेती वाला क्षेत्र था, जिसके अपने आर्थिक मतभेद थे। आंध्रप्रदेश से आज भी ऐसे कई मतभेद सुलझ नहीं पाए हैं, लेकिन हैदराबाद पर तेलंगाना का नियंत्रण है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है।

## विस्तार पाते ‘संकल्प’

# सॉफ्ट हिंदूत्व की ओर बढ़ती कांग्रेस

डा. देवेंद्र गुप्ता

कांग्रेस को सबसे बड़ी और पुरानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल था। सबसे बड़ी होने का रुतबा अब भारतीय जनता पार्टी ने कब का कांग्रेस से छीन लिया है। उसको अब पुरानी पार्टी ही बन कर संतोष करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक परिव्रक्ष में देखें तो कांग्रेस ने धर्मनिषेद्धता के मुद्दे पर बड़ी गहनता के साथ देश पर शासन करते हुए राजनीतिक दुर्घटना को अंजाम दिया। बहुसंख्यक हिंदुओं को सहिष्णुता का तो हमेशा पाठ पढ़ाया गया, परंतु

पोषण का कानून पारित हुआ।  
कदम ऐसे थे जिन्होंने प्रदेश  
वोटरों को कांग्रेस से जोड़े।  
वीरभद्र आरएसएस की  
विचारधारा को सांप्रदायिकता  
नफरत पैदा करने वाली मानते  
ऐसे विघ्नकारी संस्थान को  
बैन भी किया था। इसके बावजूद,  
चार-पांच दशक पहले अपने  
लिया था कि बहुसंख्यकों की  
जैसे देश के लिए और राजनीति  
कांग्रेस के लिए अहितकारी हो  
जाए।

## बच्चे और राजनीति

इन दिनों आम चुनाव में लगभग सभी राजनीतिक दल अपने-अपने घोषणापत्र तैयार कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षाओं के विपरीत भारत की 42 प्रतिशत जनसंख्या, यानी युवाओं और बच्चों के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है। कुछ दलों के घोषणापत्रों में टोटकों की तरह बच्चों के मुद्दे रखे तो गए हैं, लेकिन उन पर कोई सार्वजनिक बहस नहीं की जा रही। देश का संविधान कहता है कि लोकतंत्र सबका है और राज्य को सभी के लिए समान विचार अपनाना चाहिए, लेकिन हमारे राजनीतिक दलों और राजनेताओं ने इसे ऐसे समझा है कि जो मतदान करेगा या मतदान को प्रभावित करेगा, उसके बारे में उसी अनुपात में बात की जाएगी। इसलिए आम चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव, बच्चों और युवाओं के मुद्दे गौण हो जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि जो वर्ग अपना मत नहीं दे सकता वह सरकारों की प्राथमिकता में हो। जब यही राजनेता और राजनीतिक दल बच्चों को कल का नागरिक बताते नहीं थकते और उनके विकास की दलीलें देते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों पर, उनके मुद्दों पर बात करें। बच्चे, जितने कल के नागरिक हैं उतने ही आज के भी हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्व. नेल्सन मंडेला कहते थे कि किसी भी देश की प्रगति का अदाजा इस बात से लगता है कि वहां बच्चों की हालत क्या है। हमारे देश में बच्चों की हालत नाजुक है। 30 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं और इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (इफ्सी) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। अफ्सोस कि कुपोषण को समूल नष्ट करना राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में नहीं है, जबकि कुपोषण को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कुपोषण एक सामाजिक, अर्थिक, राजनीतिक कुचक्क से शुरू होता है, जिसे पांच साल में खत्म नहीं किया जा सकता, उसके लिए सतत प्रयासों की जरूरत है, लेकिन कम से कम इसे समाप्त करने की इच्छाशक्ति तो जताई ही जा सकती है। हाल ही में भोपाल में युवाओं और बच्चों ने 'सुरक्षित शहर परियोजना' के तहत बनाए गए 'उड़ान यूथ फेडरेशन' के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को राजनीतिक दलों के सामने रखा। युवाओं ने उनके रोजमरा से जुड़े ऐसे प्रश्नों को सामने रखा जो आम तौर पर राजनीतिक दलों की चिंता में शामिल नहीं होते। युवाओं ने कहा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा देकर आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। नर्सिंग की एक छात्रा अलका कुशवाह ने कहा कि पिछले चार सालों से हमारी परीक्षा ही नहीं हुई तो हम कैसे आगे बढ़ें? अधिकांश लोग अवसाद में हैं। साक्षी वर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में 'सीखो-कमाओ योजना' आई, हमने बहुत उत्साह से उसके लिए आवेदन किया, हमारा चयन भी हो गया, लेकिन लाभ ही नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर ऐसी योजनाओं का क्या औचित्य? तरुण ने कहा कि अभी तक छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन जैसे ही ये बच्चे आठवीं कक्षा पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद उन्हें शुल्क देना होता है, जिसके चलते वे बड़े पैमाने पर दाप्ताभावन दो जाते हैं।

# नक्सलवादः आरिकर कब थमेगी अपने ही युवाओं से खून की होली

योगेंद्र योगी

छत्तीसगढ़ के कांकरे में सुरक्षाबलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षाबलों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। जवान नक्सलियों के अड्डे तक पहुंचने के लिए 20 घंटे तक पैदल चले हैं। नक्सलियों के समूह को देखने के बाद पुलिस ने फयरिंग शुरू की थी। जब बूंदोंके शात हुईं, तो जंगल के पर्श पर सूखे पत्तों के बीच 29 माओवादी मृत पड़े थे। इनमें ललिता, शंकर और दूसरे कमांडर विनोद गावड़ के शर्वों की पहचान सबसे पहले की गई। मृतकों में पंद्रह महिलाएं भी थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता को केन्द्र और राज्य में भाजपा सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत कम समय में देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से इस अभियान को गति मिली है। नक्सली इलाकों में सुरक्षा बल कैंप लगाए जा रहे हैं। 19 के बाद इनकी संख्या 250 हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस से भी मदद मिल रही है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद तीन महीने में 80 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 125 गिरफ्तार हुए हैं और 150 ने आत्मसमर्पण किया है। देश के 10 राज्यों में 70 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य झारखंड जहां 16 जिले हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित

14 जिले शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में पिछले 14 सालों के भीतर 1582 नक्सली मुठभेड़ हुई है। इन मुठभेड़ के दौरान 1452 नक्सली मारे गए हैं। इस बीच 1002 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं इन हमलों में 1222 जवान शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद नक्सलियों को आशंका थी कि सरकार उनके खिलाफ अभियान तेज करेगी और हुआ भी ऐसा ही। राज्य की नई सरकार ने शान्ति का प्रस्ताव भी सामने रखा था लेकिन नक्सल नेताओं की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षाबलों को बस्तर में प्री हैण्ड कर दिया गया है। ऐसे में पिछले तीन महीनों में नक्सलियों को कई बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। अब तक जहाँ माओवादियों के बटालियन स्तर के नेता ही ढेर हुए थे तो इस बार शंकर राव जैसे डिवीजन लेवल का नेता पुलिस के गोली का शिकार हुआ है। ऐसे में नक्सली प्रदेश में पूरी तरफ से बैकफूट में हैं। अब लगातार सवाल किये जा रहे हैं कि अग्रिम कब तक छत्तीसगढ़ को इस नक्सल दंश से छुटकारा मिल पायेगा और बस्तर में खून की होली थमेगी। सरकार, सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों की संयुक्त काशिशों का परिणाम है कि पिछले एक दशक में वामपंथी अतिवाद संबंधी घटनाओं, मौतों और उनके भौगोलिक प्रसार में काफी कमी आई है। जहाँ वर्ष 2010 में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित ज़िलों की संख्या 96 थी वहीं वर्ष 2018 में प्रभावित ज़िलों की संख्या 60 रह गई है। वर्ष



2009 में जहाँ नक्सलवाद की घटनाओं और इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या क्रमशः 2258 व 1005 थी वहीं वर्ष 2018 में यह संख्या घटकर क्रमशः 833 एवं 240 रह गई। देश के जिन 8 राज्यों के लगभग 60 जिलों में यह समस्या बनी हुई है उनमें ओडिशा के 5, झारखण्ड के 14, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 2 तथा बंगाल के 8 जिले शामिल हैं। वर्ष 2015 के बाद से नक्सलियों के 90 प्रतिशत हमले लगभग चार राज्यों-छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार और ओडिशा में हुए हैं।

माओवादियों के थिंक-टैक और प्रथम पंक्ति के नेता या तो मरे जा चुके हैं या इस विचारधारा को छोड़ चुके हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के

नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' वे नाम से जाना जाता है। ज़र्मांदारों द्वारा छोड़े किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने वे लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानून सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किए गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन वे कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मज़दूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं वे खिलाफ हैं और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिये हिंसा का सहारा लेते हैं। ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरका-

के प्रति भड़काने की कोशिश करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को मुख्यतः कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे ज़मीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अपीलीय दलों द्वारा आविष्कारी उठाए गए

आधिकरण इलाक आदिवासी बहुल ह और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न ही रोजगार के अवसर। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं।

नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समातर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मज़बूत बनाया है। नक्सलवादियों की सफलता की प्रयास कर रहा है।

सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप नक्सलियों के हौसले कमज़ोर हुए हैं तथा उनके आत्मसमर्पण की संख्या लगातार बढ़ रही है। विमुद्रीकरण ने भी नक्सलियों को पहुँचने वाली वित्तीय सहायता पर लगाम लगाइ है और इसके बाद से अब तक 700 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेज़ी से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक 48877 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं को मज़बूत बनाने के लिये सरकार बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है। इसके तहत कुल 4072 टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित तौर पर पुलिस की दबाव बनाने की सक्रिय कार्रवाई और विकास बहुआयामी योजनाओं से नक्सली समस्या जड़मूल से समाप्त हो सकेगी।







## संस्कृत-खबर

भाजपा युवामोर्चा महामंडी व युवा लोधी समाज जिलाध्यक्ष रवि सिंगोर के जन्मदिन में पर बधाई देने पहुंचे युवा लोधी समाज प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंगोर



**पाटन (समय दर्शन)**। रवि सिंगोर का जन्मदिन उनके गृहग्राम साकरा सहित आसपास के ग्राम मोतीपुर खमरिया में धूमधाम से मनाया गया।

इस दौरान जिलाउपाथ्क बत्तन सिंगोर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष उमेश साहू आनंद पांडे राधे साहू हर्षद राम साहू ऋषभ राजपूत, सरपंच पर्ति यशवंत जंगड़े जी, टिकट्ट सिंगोर, तुलाराम सिंगोर, कमल सिंगोर, भोजराम सिंगोर, ब्रह्म यादव के जराम वैष्णवकामता सिंगोर, मनीष कौशले वरुण सिंगोर, मुहु सिंगोर छोटू यादव विनेन्द्र युद्ध तुलेश सिंगोर मोहन सिंगोर लवकुश सिंगोर हेन्ड सिंगोर, नरोत्तम सिंगोर, साहिल सिंगोर छोटे नारेश सिंगोर चुम्पन सिंगोर लक्ष्मीनारायण ब्रवण सिंगोर मुकेश सिंगोर परस सिंगोर सोनू सिंगोर, नारायण चन्द्रकार खिलेश विश्वकर्मा, सत्यम निर्मलकर, संजय यदू भुपेन्द्र पटेल सहित अन्य लोगों मौजूद रहे। रवि सिंगोर ने सभी को आभार करते हुए कहा की मेरे जन्मदिन पर आप सभी प्रियजनों द्वारा दिए गए सभी विचारों लिए और अनुकूल संदेशों के लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं मैं बहुत भाव्याली हूं किंवद्दन मेरे पास आप जैसे शुभचक्त दोस्तों का इतना अद्भुत समूह है। आप सभी ने सचमुच मेरा जन्मदिन को यादगार दिन बना दिया कहते हुए आभार किया।

**आकाश में गुब्बारे से जिला प्रशासन ने भेजा बुलावा घर आवे संगी**



**सारंगढ़ बिलाईगढ़ (समय दर्शन)**। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पवनी के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। कलेक्टर श्री साहू ने इस अवसर पर जिले से पलायन किया नारायणों को किया वह बुलावा के लिए प्रतीकों के तौर पर तीन रंगों से भरा गुब्बारा उन तक आकाश के माध्यम से भेज रहे हैं। इस गुब्बारे में लिखा हमारा सदैरा स्थान है कि \*घर आवे संगी\*। घर बुलाने का जिला प्रशासन का अपील है कि वह अपने घर आकर 7 मई 2024 को मतदान करने अपने संवंधित मतदान केंद्र में जाए और लोकतंत्र के इस महान पर्व में अपनाया भागीदारी निभाएं। कलेक्टर श्री साहू ने अपने उद्घाटन में सभी नागरिकों को कहा कि वह अपने साथ-साथ घर परिवार, आस-पास और अपने जुड़े जुड़े लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर स्वीप नोडल अधिकारी हरिसंकर चौहान, एसडीएम बिलाईगढ़ डॉ. सिंधारा तिवारी, सीईओ बिलाईगढ़ प्रतीक प्रधान सहित स्थानीय पत्रकार एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

**फ्रेंडली पुर्वबॉल मैच खेल कर दिए मतदान अवश्य करने का संदेश**



**भिलाईनगर (समय दर्शन)**। जिलाधीश ऋचा प्रकाश चौधरी ने फुटबॉल पर किंक मार कर सेक्टर 2 फुटबॉल मैदान में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत खेले गए फ्रेंडली फुटबॉल मैच का शुभारंभ किये। रोमांचक मैच में आईजी, एसपी, भिलाई व दुर्ग निगम आयुक, जिला पंचायत सीडीओ को मैदान में सधे हुए खिलाड़ियों को तरह खेलता देख दर्शकों ने तालिया से उनका उत्साह वर्धन करते रहे। मैच के समाप्ति पर कलेक्टर ने दीप के कानों तथा सदैरा के उपस्थित का उत्साह दिया।



रहे हैं उनके सहयोग के लिए प्रतिवर्ष बसना प्रखण्ड द्वारा सहयोग राशि विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जाता है। जात हो कि, बनाचल में संचालित साधु, संतों, रिधि, मुनियों व वैदिक संस्कृत की कमिशनिंग कार्यक्रम के लिए जिले के निवासियों को शुरुआती राशि जुटायी गयी, और व्यापारियों को जुटाया गया। इस कार्यक्रम को प्रखण्ड द्वारा आयोजित किया जाता है।

संचालन के द्वारा आयोजित किया जाता है।

बसना (समय दर्शन)। बसना में शाही संघर्ष के ग्राम हबेकांया में आयोजित एष्ट्रहिनाम संकीर्तन नामयज्ञ में सुख्य अतिथि बिधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल ने कहा कि एष्ट्रहिनाम संकीर्तन नामयज्ञ का आयोजन गौरव की बात है। हरि किरतन से क्षेत्र में सुख समृद्धि, खुशहाली व विकास के साथ भारी विकास होने के लिए अग्रवाल नामयज्ञ का आयोजन गौरव की बात है। इस दौरान उहाँने लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्यारोपी रुपुकुमारी चौधरी को प्रचण्ड मतों से जीताकर बसना का नाम रौशन करने की अपील की, और मोदी जी के गारंटी और योगीनाओं को बताया।

इस अवसर पर सरपंच त्रिलोचन भोई, ग्राम गाँवीय अग्रवाल द्वारा, बंशी भोई, बिनो भोई, गणेश भोई सहित अन्य समानितजन मोजूद थे।

## बसना प्रखण्ड द्वारा वनवासी कल्याण आश्रम के लिए जुटाया गया राशि



रहे हैं उनके सहयोग के लिए प्रतिवर्ष बसना प्रखण्ड द्वारा सहयोग राशि विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जाता है। जात हो कि, बनाचल में संचालित साधु,

संतों, रिधि, मुनियों व वैदिक संस्कृत की कमिशनिंग कार्यक्रम के लिए जिले के निवासियों को शुरुआती राशि जुटायी गयी, और व्यापारियों को जुटाया गया। इस कार्यक्रम को प्रखण्ड द्वारा आयोजित किया जाता है।

संचालन के द्वारा आयोजित किया जाता है।

बसना (समय दर्शन)। बसना में शाही संघर्ष के ग्राम हबेकांया में आयोजित एष्ट्रहिनाम संकीर्तन नामयज्ञ में सुख्य अतिथि बिधायक डॉ. सम्पत अग्रवाल ने कहा कि एष्ट्रहिनाम संकीर्तन नामयज्ञ का आयोजन गौरव की बात है। हरि किरतन से क्षेत्र में सुख समृद्धि, खुशहाली व विकास के साथ भारी विकास होने के लिए अग्रवाल नामयज्ञ का आयोजन गौरव की बात है। इस दौरान उहाँने लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्यारोपी रुपुकुमारी चौधरी को प्रचण्ड मतों से जीताकर बसना का नाम रौशन करने की अपील की, और मोदी जी के गारंटी और योगीनाओं को बताया।

इस अवसर पर सरपंच त्रिलोचन भोई, ग्राम गाँवीय अग्रवाल द्वारा, बंशी भोई, बिनो भोई, गणेश भोई सहित अन्य समानितजन मोजूद थे।

**विधानसभा 64-दुर्ग शहर के लिए माकपोल हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 को**

रहे हैं उनके सहयोग के लिए प्रतिवर्ष बसना प्रखण्ड द्वारा सहयोग राशि विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जाता है। जात हो कि, बनाचल में संचालित साधु,

संतों, रिधि, मुनियों व वैदिक संस्कृत की कमिशनिंग कार्यक्रम के लिए जिले के निवासियों को शुरुआती राशि जुटायी गयी है, उत्तम प्रधारी अधिकारी गाँवीय अधिकारी गाँवीय अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 अप्रैल को सुखुर 11 बजे से खिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाविद्यालय (बीआईटी) दुर्ग में आयोजित की गई है। माकपोल हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 अप्रैल को सुखुर 11 बजे से खिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाविद्यालय (बीआईटी) दुर्ग में आयोजित की गई है। माकपोल हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों की शुरुआत ग्राम सलीहा के उत्तम संघ से बात कर दिया गया।

विधानसभा 64-दुर्ग शहर के लिए नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 को

रहे हैं उनके सहयोग के लिए प्रतिवर्ष बसना प्रखण्ड द्वारा सहयोग राशि विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जाता है। जात हो कि, बनाचल में संचालित साधु,

संतों, रिधि, मुनियों व वैदिक संस्कृत की कमिशनिंग कार्यक्रम के लिए जिले के निवासियों को शुरुआती राशि जुटायी गयी है, उत्तम प्रधारी अधिकारी गाँवीय अधिकारी गाँवीय अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 अप्रैल को सुखुर 11 बजे से खिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाविद्यालय (बीआईटी) दुर्ग में आयोजित की गई है। माकपोल हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों की शुरुआत ग्राम सलीहा के उत्तम संघ से बात कर दिया गया।

विधानसभा 64-दुर्ग शहर के लिए माकपोल हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 को

रहे हैं उनके सहयोग के लिए प्रतिवर्ष बसना प्रखण्ड द्वारा सहयोग राशि विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जाता है। जात हो कि, बनाचल में संचालित साधु,

संतों, रिधि, मुनियों व वैदिक संस्कृत की कमिशनिंग कार्यक्रम के लिए जिले के निवासियों को शुरुआती राशि जुटायी गयी है, उत्तम प्रधारी अधिकारी गाँवीय अधिकारी गाँवीय अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 अप्रैल को सुखुर 11 बजे से खिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाविद्यालय (बीआईटी) दुर्ग में आयोजित की गई है। माकपोल हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों की शुरुआत ग्राम सलीहा के उत्तम संघ से बात कर दिया गया।

विधानसभा 64-दुर्ग शहर के लिए माकपोल हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 को